विचार बिन्दु

अति क्रोध, कटु वाणी, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीचों का संग और अकुलीन की सेवा, ये नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। -चाणक्य नीति

सरकारी सेवा में भर्ती करने वाली संस्थाओं में सुधार किया जा सकता है, बशर्ते सरकार चाहे

राजकीय सेवाओं में सेवाओं के भर्ती और सेवा शर्तों से सम्बंधित मूलभूत प्रावधान संविधान के खंड 14 के अध्याय 1 व 2 में दिए हैं। इन प्रावधानों के अध्यधीन केंद्र व राज्य सरकारें भर्ती नियम, प्रक्रियाएँ तय करती है।

राजस्थान में राज्य सेवाओं व अधिनस्थ राज्य सेवाओं, (जिनसे राज्य सेवाओं में पद्दोन्ति होती है) उनमें भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो एक संवैधानिक निकाय है। लिपिक वर्ग, पटवारी, लेखा वर्ग कार्मिकों व अन्य समक्ष सेवाओं में भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया हुआ है।

लम्बे समय से इन निकायों की पब्लिक इमेज उच्चस्तरीय विश्वस्नीयता वाली नहीं कही जा सकती है। भर्ती के विज्ञापन और नियुक्तियों के बीच 3 से 5 साल का अंतराल आम बात हो गई। पेपर तैयार करने वालों की जानकारी लीक, पेपर प्रिंट करने वाली प्रेस की जानकारी लीक होने, परीक्षा से पहले पेपर लीक, अंसरशीट्स चेकिंग को लेकर एक्जमीनर्स की सूचना लीक होने व गड़बड़ियों की बातें, प्रश्नों की गलत फ्रेमिंग-ऐसे प्रश्न रखना जिनको सामान्यत: कोई जानता नहीं या प्रदेश के किसी छोटे से भू-भाग से सम्बंधित हों, गलत उत्तर आदि सास्वत व्याधियां बन गई हैं। परीक्षा केंद्रों के चयन व इन केंद्रों पर तैनात किए जाने वाले कार्मिकों आदि पर अंगुलियां उठती रही है।

इन निकायों की कार्य प्रणाली से भर्तियां कोर्ट दर कोर्ट में चेलेंज होती रहती है और नियुक्तियां अटकी रहती हैं।

शिक्षक वर्ग की भर्ती परीक्षाएं कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कई बार आरपीएससी के माध्यम से करवाई गई हैं।

शिक्षा बोर्ड का मुख्य काम स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए 10वीं व 12 वीं की परीक्षाएं आयोजित करना और परिणाम घोषित करना ही है। इसकी कार्य प्रणाली से भी लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है। इसलिए इसकी भी प्रमाणिकता व शुचिता उतनी ही आवश्यक है जितनी आरपीएससी व अधीनस्थ सेवाओं के किए गठित सेवा आयोगों की होनी चाहिए।

राजकीय सेवाओं में भर्तियां नियमित रूप से हों और उनकी गोपनियता, शुचिता व प्रमाणिकता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इन शीर्ष संस्थाओं के शीर्ष कर्ताधर्ताओं और संस्थाओं की कार्यप्रणाली में उच्चश्रेणी की निष्ठा, प्रमाणिकता, यथा सम्भव पारदर्शिता हो।

इन संस्थाओं का स्वरूप इनके अध्यक्ष, सदसस्य गण, अधिकारियों व सहयोगी स्टाफ से मिलकर बनता है। सैंकड़ों की संख्या में काम करने वाले कर्मचारियों में सबकी निष्ठा, प्रमाणिकता की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता किन्तु इनके शीर्ष पर बैठाए जाने वाले अध्यक्षों, सदस्यों, व शिर्ष अधिकारियों के सम्बंध में तो ऐसा किया ही जा सकता।

अगर इन आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, व सचिव निष्ठावान हों तो पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्र व वहां इन्विजिलेटर्स, पर्यवेक्षकों के चयन, अंसरशीट्स की जांच, मार्किंग और व्यक्तित्व परीक्षण मार्किंग की गोपनियता, शुचिता, प्रमाणिकता पर प्रश चिन्ह उठ ही नही सकते।

यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो यह बहुत ही आसान कार्य है। इसके लिए इन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के लिए, सरकार को अपना असीमित स्वविवेकीय अधिकार, कुछ मर्यादित करना पड़ेगा। यदि इन नियुक्तियों में जातिवाद, व्यक्तिगत निष्ठा आदि को ही महत्व होगा तो इन निकायों की विश्वसनीयता समाप्त होगी ही--जो शनैः शनैः हो रही है!!

चूंकि इन निकायों की कार्य प्रणाली से लाखो नव युवक-युक्तियों का और उनके परिवारों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए ऐसा होना ही चाहिए। संविधान और सम्बंधित कानूनों-नियमों के अनुसार इन अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है। यह कोई छिपा रहस्य नहीं कि अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति मात्र उनकी निष्ठा, प्रमाणिकता, एफ्फिसियनसी, लोकसेवा- समाज सेवा, अथवा शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट पहचान को आधार बनाकर ही नही की जाती।

इन पदों पर नियुक्ति व्यक्ति विशेष व राजनीतिक दल विशेष की विचारधारा के प्रति निष्ठा, राजनीतिज्ञों की सिफारिश पर और जातीय आधार से चुनावी लाभ लेने के लिए की जाती रही है। पिछले बीसेक साल से इसके लिए विशेष शब्द प्रयुक्त होने लगा-- सोसल इंजिनियरिंग।

लंबे समय अथवा अत्यंत कम समय के लिए के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष रखना आम बात हो गई। इन सब से किसी भी संस्थान की साख में गिरावट तो आती ही है।

क्या सेवाओं में नियुक्तियों की अनुशंसा करने वाले निकायों में नियुक्तियों को ज्यादा पारदर्शी, विश्वशनीय नहीं बनाया जा सकता?

यदि सरकार की इच्छया शक्ति हो तो यह बहुत ही आसान कार्य है। इसके लिए इन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के लिए, सरकार को अपना असीमित स्वविवेकीय अधिकार, कुछ मर्यादित करना पड़ेगा। यदि इन नियुक्तियों में जातिवाद, व्यक्तिगत निष्ठा आदि को ही महत्व होगा तो इन निकायों की विश्वसनीयता समाप्त होगी है--जो शनैः शनैः हो रही है!!

यदि सरकार इन नियुक्तों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया या ऐसी ही कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित करे तो इन निकायों की विश्वसनीयता बनी रहेगी::--

(1) इन पदों पर नियुक्तियों के लिए विश्वसनीय सर्च कमेटीयां बनाई जाए। प्रथम सर्च कमेटी विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा,लोक सेवाएं,समाज सेवा आदि क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करे। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्रों के सक्षम, निष्ठावान, लोगों का समावेश हो। चूंकि आधे सदस्य राज्य की सेवाओं में अनुभव रखने वाले होने चाहिए, इसलिए इनके लिए 55-58 साल से ज्यादा उम्र वाले ईमानदार, योग्य अधिकारियों की सूची विभागों के प्रमुख सचिवों से ली जा सकती है।

(2) दूसरी उच्च स्तरीय सर्च कमेटी इस सूची को पब्लिक डोमेन में डाल कर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करें। इससे इन लोगों के सम्बंध में कई अच्छी-बुरी नई बातों का पता चल सकता है। राज्य सेवा से जुड़े अधिकारियों के सेवा रिकार्ड भी देखा जा सकता है। राज्य सेवाओं से भिन्न लोगों के सम्बंध में गोपनीय जांच करवाकर उनकी कार्य के प्रति व चारित्रिक ईमानदारी, कमपीटेंसी आदि के आधार पर सयूटेबिलिटी जांची जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त फीड बैकव अन्य उचित मानदण्डों के आधार पर प्रथम सूची में से यह सर्च कमेटी 10 से 20 व्यक्तियों की सूची सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करे।

(3) उपरोक्त सूची में से सरकार ऐसे व्यक्तियों का नियुक्ति के लिए चयन कर ले जिनका कम से कम दो साल सेवा काल आयोग में हो। यह दो साल के कार्यकाल की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरांत केंद्र के कुछ सचिवों और विभगों के अध्यक्षों के लिए अपनाइ भी जाती है।

इस प्रक्रिया को तय करने में किसी संवैधानिक व नियोमों में संसोधन की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो तुरंत इस प्रकार की उचित नीति अपनाई जा सकती है।

-अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह,
आई.ए.एस. (से.नि.)

एनपीएस की जगह ओपीएस पर क्यों लौटी सरकार?

हर पढ़े-लिखे व्यक्ति का सरकारी नौकरी में जाना एक सपना होता है, सिवाय कुछ व्यवसायिक सोच रखने वाले निड़र लोगों को छोड़कर। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मानों हर पढ़ा-लिखा युवा सरकार की नौकरी करना ही अपना परम धर्म मानने लगा है।

हां, यह बात सही है कि सरकारी नौकर प्रतिवर्ष सैंकड़ों की संख्या में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा भ्रष्ट आचरण के कारण पकड़े भी जाते हैं किंतु फिर भी सरकार को अपने इन्हीं सरकारी कर्मियों का सहारा लेना पड़ता है। आपको याद होगा वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2003 में सरकारी शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की बेरुखी के कारण ही गहलोत 2003 में सत्ता से बाहर हुये थे।

करीब 18 वर्ष पूर्व जब फैमिली पेंशन योजना बंद कर न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी, तब भी प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ही थे। ऐसे में लोगों की चर्चा में पहली बात यही सामने आ रही है कि क्या ओपीएस बहाल करने से अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार 2023 में रिपीट होगी?

गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों का दिल जीतने का जो दांव चला है, उसके परिणाम या दुष्परिणाम तो 2030 के बाद ही मिलने शुरू होंगे, क्योंकि एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों के रिटायर होने का समय तभी आरम्भ होगा, किंतु फिर भी वर्तमान परिस्थितयों में इस पर चर्चा करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में गहलोत ने प्रदेश को 18 साल पीछे धकेल दिया है? या फिर अब तक का सबसे बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है?

सवाल यह उठता है कि जब राज्य पर बड़े पैमाने पर कर्ज है और किसान भी कर्जमाफी के लिये बीते 3 साल से वादे के मुताबिक मांग कर रहे हैं, तब ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि अशोक गहलोत को अपने कदम 18 साल पीछे खींचने पड़े?

मैं पिछले दिनों जब यूपी में ग्रांउड रिपोर्ट कर रहा था, तब कई सरकारी कर्मचारियों के मुंह से इसका जिक्र सुना कि इस बार सपा की सरकार बननी चाहिये, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया है। यूपी में भी 2004 के बाद नियुक्ति करीब 7 लाख कर्मचारी हैं, जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जबकि, यहां राजस्थान में बिना किसी वादे के ही अशोक गहलोत सरकार ने देश में पहली बार यह कदम उठाकर एक लकीर खींच दी है। अब अन्य राज्यों में भी ओपीएस के लिये मांग बढ़ेगी।

किंतु आपको याद होगा न्यू पेंशन स्कीम की सिफारिश करने वाली कमेटी ने कहा था कि इससे देश में संगठित कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र में काम

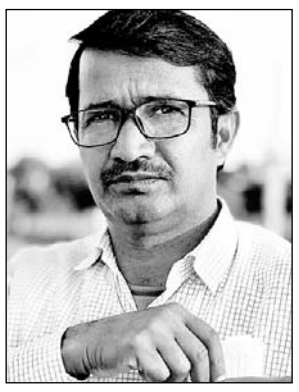

रामगोपाल जाट

करने वाले कर्मचारियों में समानता आयेगी और सामाजिक भेदभाव में बड़े पैमाने पर कमी आयेगी।

आपको यह जानना बेहद जरुरी है कि फैमिली पेंशन अप्रैल 2004 में बंद कर दी गई थी, यानी उसके बाद सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन मिलती है, जबकि उससे पहले के कर्मचारियों को फैमिली पेंशन मिल रही है। इस न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों की परेशानी यह है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं, यह तय ही नहीं है।

एनपीएस के तहत सरकारी कर्मी के वेतन से 10 फीसदी राशि काटी जाती है और इतनी ही राशि सरकार के अंश की होती है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक यह राशि काटी जाती है, जिसमें से 70 प्रतिशत राशि कर्मचारी को रिटायर होने पर नकद दी जाती है और बाकी 30 प्रतिशत पेंशन फंड के लिए जमा किए जाने का प्रावधान है, जिसमें से उन्हें जीवित रहने तक आंशिक पेंशन दी जाती है।

अप्रैल 2004 से पहले नौकरी में भर्ती हुए कर्मचारियों को फैमिली पेंशन मिल रही है। इसमें पेंशन के नाम पर उनके वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाती। रिटायरमेंट के वक्त अंतिम माह में जो वेतन देय होता है, उसकी 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में तय हो जाती है। यह राशि उन्हें जीवित रहने तक मिलती है और उसके बाद उसकी 50 प्रतिशत राशि पेंशन के तौर पर कर्मचारी के आश्रित को मिलनी प्रारम्भ हो जाती है।

राजस्थान सरकार के निर्णय के प्रभाव की बात की जाये तो राज्य में एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुये करीब 3 लाख कर्मचारी ओपीएस के दायरे में आयेंगे। इसके साथ ही तकरीबन 4 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में पहले से ही हैं। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से वर्तमान वेतनमान के हिसाब से भी राज्य पर प्रतिवर्ष करीब 180 करोड़ रुपयों का वार्षिक भार आयेगा। और जब 2030 के बाद पेंशन आरम्भ होगी, तब यह भार लगभग तीन से चार गुणा तक बढ़ने का अनुमान है।

अब सवाल यह भी उठता है कि राज्य सरकारें जब यह दावा करती हैं कि हमने इतनी संख्या में सरकारी नौकरी दी हैं, तो सवाल यह खड़ा होता है कि बीते 18 साल में ओपीएस से वंचित केवल 3 लाख सरकारी कर्मी ही कैसे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में हैं। वर्तमान सरकार भी दावा कर रही है कि बीते 3 साल में एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। तो क्या यह सवाल नहीं उठता है कि उससे पहले के 15 साल में क्या केवल 2 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली थी?

यह बात सही है कि किसान, निर्माण कार्यों के मजदूर, खानों में काम करने वाले, पशुपालन करने वाले और अन्य किसी भी कार्य के द्वारा देश के विकास में मददगार कोई भी कर्मशील व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर असुरक्षित नहीं रहना चाहता, किंतु सरकारी कर्मचारियों की भांति संगठित नहीं होने के कारण उनपर सरकारें ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।

सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुये ही अशोक गहलोत सरकार ने शायद तत्कालीन सरकार का 18 साल पुराना निर्णय बदला होगा। हालांकि, इसमें चुनावी जोखिम अवश्य है। गहलोत पिछले कई माह से सरकार रिपीट होने का दावा करते रहे हैं, जिसका एक कारण ओपीएस बहाल करना भी हो सकता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर सात लाख परिवारों के करीब 21 से 28 लाख मतदाता प्रभावित होते हैं।

रामगोपाल जाट
वरिष्ठ पत्रकार

बीकानेर की बेटी शिवांगी और वर्णिका ने बताई यूक्रेन की आपबीती, बंकर में छिपकर गुजारीं रातें

खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर बीकानेर के विवेक सोनी सहित दर्जनभर स्टूडेंट्स अब भी फंसे हुए हैं

बीकानेर,(कासं)। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जान बचाकर दो बेटियां बुधवार को बीकानेर पहुंच गई। इन्हीं में एक शिवांगी शर्मा दिल्ली फ्लाइट से बीकानेर आई। शिवांगी बताती है कि पोलैंड के रास्ते भारत आने से पहले उसे पानी पीकर दिन गुजारना पड़ा। वहीं, कई किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन तक आए। यूक्रेन में इन दिनों अफरातफरी मची हुई है। वो खुश है कि केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से वो बीकानेर आ गई हैं।

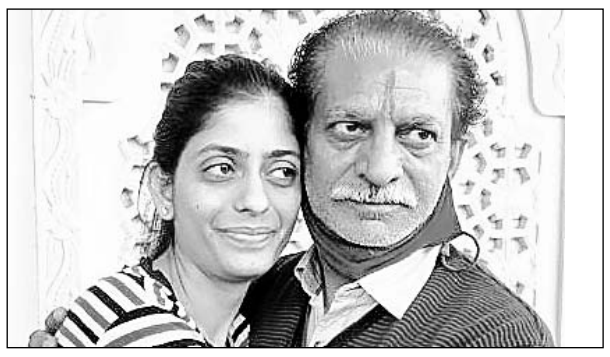

दिल्ली से बीकानेर पहुंची शिवांगी अपने पापा के साथ।

यूक्रेन से लौटी तुलसीराम कालरा की बेटी वर्णिका परिवार के साथ।

बातचीत में शिवांगी ने बताया कि यूक्रेन की ईस्ट साइड पर हमला हुआ है, वहीं पर खतरा है। खार्किव और कीव ईस्ट साइड में ही हैं वहीं, लवीन और तड़ोपे जैसे एरिया में कोई हमला नहीं है। वहां पर अफरा-तफरी मची हुई है। लवीन में भी लोग बंकर में छिपे हुए हैं। बार बार सायरन बजता है। लोग घरों की लाइट्स नहीं जला पा रहे। बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा निकलना आसान था, इसलिए आ गए। हालांकि हमें भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।

शिवांगी बताती है कि इंडियन एम्बेसी सभी का सहयोग कर रही है। दरअसल, जिन एरिया में ज्यादा समस्या है, वहां एंबेसी के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पोलैंड पहुंचने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां भारतीय एंबेसी के अधिकारी तैयार खड़े हैं। हमें सभी सुविधाएं दी गई। भारत पहुंचने के साथ ही राजस्थान सरकार के अधिकारी मिल गए। शिवांगी का कहना है कि भारत में मेडिकल कॉलेज की फीस एक करोड़ रुपए तक है। ऐसे में अच्छे मार्क्स लेकर भी एडमिशन नहीं पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए विदेश ही विकल्प है। यूक्रेन में पढ़ाई पच्चीस लाख रुपए तक में हो जाती है, जबकि भारत में चार गुना रुपए लग रहे हैं। यूक्रेन से आयी भारतीय छात्रा एमबीबीएस तीसरे वर्ष की छात्रा वर्णिका कालरा भी बीकानेर आ गई हैं। जयनारायण व्यास कॉलोनी निवासी तुलसीराम कालरा की बेटी वर्णिका ने बताया कि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रारंभ हुआ है। तभी से सब परेशान थे। भारतीय एंबेसी के सहयोग से वो बीकानेर तक पहुंच सके।

■ पोलैंड पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं है वहां भारतीय एंबेसी के अधिकारी सुविधाएं दे रहे हैं

वर्णिका के बीकानेर पहुंचने पर घर पर उसका स्वागत किया गया। भारतीय दूतावास से सहयोग नहीं मिलने से दुखी स्टूडेंट्स अब अपने बूते ही कीव व खार्किव से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हैं। ये स्टूडेंट्स ट्रेन, बस या फिर केब से निकल तो रहे हैं लेकिन रास्ते में लूट, फायरिंग और रूसी सैनिकों से मारपीट का भय इन्हें सता रहा है। इन्हीं में कुछ बीकानेर के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं।

बीकानेर की आकांक्षा और माधुरी का कहना है कि खार्किव को छोड़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं। इसमें बीकानेर की कुछ लड़कियां शामिल है। लगभग दस किलोमीटर पैदल चलने के बाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते में गोलियां और बमबारी की आवाजें सुनाई देती रही। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां इतनी जबर्दस्त भीड़ थी कि ट्रेन तो दूर रेलवे स्टेशन में घुस पाना मुश्किल था। तीन बार ट्रेन आई और चली गई लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स वहीं खड़े रह गए। बाद में जैसे-तैसे इस ट्रेन से हम निकल पाए हैं। ट्रेन पूरी तरह फ्री है लेकिन सौ से पांच सौ डॉलर की कीमत चुकानी पड़ रही है। भारतीय एंबेसी भी स्टूडेंट्स का सहयोग करने में अब असहाय हो गई है। रूसी हवाई हमले उन लोगों पर किए जा रहे हैं, जो सड़क पर हैं। ऐसे में किसी बस या केब में जाने पर उन पर भी हमले की आशंका रहती है। उधर, खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर बीकानेर के विवेक सोनी सहित दर्जनभर स्टूडेंट्स अब भी फंसे हुए हैं। बंकर में होने से सुरक्षित हैं लेकिन भोजन की व्यवस्था बमुश्किल हो पा रही है।

जीवनदायी पेड़ों के बारे में संवेदनशील होने की ज़रूरत है!

सरसरी तौर पर देखेंगे तो जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वह एक अतिशयोक्ति जैसी लग सकती है, पर जिन लोगों ने इस बारे में लिखा है वे लोग प्रसिद्ध पत्रकार अनिता प्रताप जैसे जिम्मेदार तथा वैज्ञानिक मानसिकता वाले लोग हैं। इसी तरह एक सर्जन डॉक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बगीचे में एक आम के पेड़ का पालन-पोषण किया था, वे रोज सुबह-शाम उस पेड़ से बतियाते थे। लोग उनकी इस हरकत को सनक मानते थे पर पेड़ जब मीठे-मीठे आमों से लद जाता तो सब कुछ भूल कर वे सब भी उनके स्वाद का आनंद लेते थे। एक दिन डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों ने उनकी भावना के अनुरूप पेड़ को खाद-पानी दिया, पर पूरे दो वर्ष तक पेड़ पर कोई फल नहीं आया, मानो पेड़ अपने मित्र के जाने से विषाद में डूब गया हो। दो साल बाद फल तो आने लगे पर संख्या और स्वाद दोनों में बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले वाली बात नहीं रही थी। पेड़ फिर कभी भी पहले जैसा फला-फूला नहीं।

ज्यों-ज्यों विज्ञान का विकास हो रहा है नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कनाडा के जंगलों में शोध करने वाली पर्यावरण प्रेमी सुजैन सिमार्ड ने अपना पूरा जीवन पेड़, पौधों तथा वनस्पतियों के अध्ययन को समर्पित कर दिया है। सुजैन का मानना है कि पेड़ बहुत कुछ पहचानते हैं, वे चीत्कार करते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, विषाद में डूबते हैं। सिमार्ड ने अपने अध्ययन द्वारा बताया है कि विभिन्न पेड़-पौधे धरती के नीचे फंगस के एक वृहद जालनुमा तंत्र के माध्यम से एक-दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जब किसी पेड़ के अंदर कीड़े लग जाते हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला कर देता है तो

डॉ रामावतार शर्मा

स्वस्थ पेड़ वहां पर कुछ विशिष्ट एंजाइम्स भेजते हैं ताकि हमलावरों को नष्ट किया जा सके। अकाल की स्थिति में पानी का भी आपसी आदान-प्रदान किया जाता है और विशिष्ट जीवन रक्षक तत्व भी आपस में बांटे जाते हैं। टमाटर के पौधे के पास यदि लहसुन लगाया जाए तो पौधा प्रसन्न होकर तेजी से बढ़ता है क्योंकि बहुत से कीड़े लहसुन के पास नहीं आते, पर मटर का मिजाज जरा अलग है। मटर के पास लहसुन लगाने से मटर का विकास बाधित होता देखा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि वहां पर भी सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मौजूद हैं।

पेड़, पौधों और जंगलों का अपना-अपना जीवंत समाज होता है जिसमें ढाणी, गांव, नगर और महानगर होते हैं, जिनमें तरह-तरह के जीव-जंतु भी अपना जीवन बिताते हैं। इसे जीव विविधता कहा जाता है। इस सारे तंत्र में तरह-तरह के वायरस और बैक्टीरिया वनों और पेड़ों के झुण्डों द्वारा चारों तरफ विसर्जित होने से रोके जाते हैं। अब यदि वनों की बेतहाशा कटाई की जाती है या फिर गांवों, कस्बों और शहरों को वृक्ष विहीन किया जाता है तो प्राकृतिक संतुलन नष्ट होता है, जिसके फलस्वरूप वायरस तेजी से चारों तरफ फैल कर महामारियां को जन्म दे सकते हैं। याद रखिए पेड़-पौधों के अभाव में जीवन पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

हमने पेड़ों को काट कर शानदार सोफा बना लिया जिस पर बैठने की हमें फुरसत नहीं है, बड़े-बड़े बिस्तर बना लिए, जिन पर हमें नींद नहीं आती। आवश्यकता के अनुरूप आप उम्रदराज पेड़ों का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई अपराधबोध नहीं होना चाहिए पर जरा पेड़ों को लगाने के बारे में भी तो सोचिए। एक चार फुट का पेड़ सामान्यत: पचास रुपए में मिल सकता है। यदि हर भारतीय हर साल एक पेड़ लगा कर उसे विकसित करता है तो साल में एक सौ चालीस करोड़ पेड़ खड़े हो सकते हैं। आवश्यकता जागरूकता की है, लगन की है।

डॉ रामावतार शर्मा,
चिकित्सक एवं लेखक

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 3 मार्च, 2022

फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2078, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:56 तक, साध्य योग रात्रि 3:28 तक, किस्तुघ्न करण दिन 10:21 तक, चन्द्रमा रात्रि 8:03 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-मकर, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:20 तक, चर 11:12 से 12:39 तक, लाभ-अमृत 12:39 से 3:32 तक, शुभ 4:58 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:53, सूर्यास्त 6:25

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन

धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कन्या

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना बनेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सोच-विचार होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।